'पंच' होंगे आंगनबाड़ी के 'परमेश्वर'

संजय त्रिपाठी/एसएनबी

पटना। अब 'पंच' ही सूबे के अस्सी हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के 'परमेश्वर' होंगे। नीतीश सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की कुंजी जनता के हाथों सौंपने जा रही है। जनता खुद मिलकर समिति बनाएगी और यह समिति आंगनबाड़ी केन्द्रों की मॉनीटरिंग करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सेविका की गलती पर उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा भी करेगी। यह कवायद आंगनबाड़ी केन्द्रों में भ्रष्टाचार और पोषक तत्वों की बंदरबाट रोकने के लिए की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के बेहतर संचालन के लिए नयी नियमावली तैयार की है। फिलहाल इस नियमावली का विधि विभाग अध्ययन कर रहा है। विधि विभाग से संचिका लौटने के बाद नयी नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। खास है कि सूबे में अस्सी हजार आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। एक केन्द्र से 99 लोग लाभान्वित होते हैं। इस तरह करीब अस्सी लाख लोग आंगनबाड़ी केन्द्रों से जुड़े हैं। प्रत्येक केन्द्र पर सरकार 10973 रुपये खर्च कर रही है, फिर भी आंगनबाड़ी केन्द्रों की दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों को लेकर प्रखंड स्तर से लेकर

जनता के व्यापक हित में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जनता ही आंगनबाड़ी केन्द्रों की मॉनीटरिंग करेगी। सेविकाओं से जवाब तलब करेगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाएगी

-परवीन अमानुल्लाह
समाज कल्याण मंत्री

मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक में शिकायतें आती रहती हैं। ऐसी शिकायतों को हमेशा के लिए दूर करने, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार के (शेष पेज 15 पर)

▶ आंगनबाड़ी केन्द्रों की मॉनीटरिंग अब होगी स्थानीय लोगों की समिति के जिम्मे ▶ समाज कल्याण विभाग ने तैयार की नयी नियमावली ▶ सेविका को बर्खास्त करने की अनुशंसा भी कर सकती है समिति, सूबे में हैं करीब 80 हजार केंद्र